आकाशवाणी शिमला

13.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार :-

- प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीपीएस एक्ट को किया निरस्त– सभी मुख्य संसदीय सचिवों की सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म करने के आदेश।
- भाजपा ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत–मुख्य संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्त विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–प्रदेश में सतत विकास के लिए इको–टूरिज्म को बढ़ावा देना आवश्यक।
- तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा–राज्य विद्युत बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं सुधारात्मक कदम।

हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के फैसले के तहत प्रदेश में सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को दी जा रही सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। अब ये 6 मुख्य संसदीय सचिव केवल विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी जिनमे आशीष बुटेल, किशोरीलाल, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने सीपीएस नियुक्ति पर सीपीएस एक्ट 2006 का हवाला दिया था जिस पर लम्बी बहस के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बैंच न्यायाधीश बीसी नेगी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने आज अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के वकील वीर बहादुर ने पत्रकारों से बातचीत में फैसले के बारे में जानकारी दी। उच्च न्यायालय में एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

जयराम

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को अवैध ठहराने और उनकी सभी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से छीनने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा यह फैसला असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण तरीके से लिया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार द्वारा तानाशाही पूर्ण तरीके से यह नियुक्ति अपने विधायकों को खुश रखने के लिए की गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के फैसले के खिलाफ थी और सरकार के इस फैसले को न्यायालय मे चुनौती दी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जान बूझकर सीपीएस की नियुक्ति की जिससे प्रदेश के राजस्व पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा।

अनुराग

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने संबंधी न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस सरकार द्वारा अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने की नीति जगजाहिर हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व में भी कांग्रेस सरकार के समय सीपीएस पद को कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाई थी बावजूद इसके इस सरकार ने अड़ियल रवैया दिखाते हुए सीपीएस की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता की चिंता छोड़कर सिर्फ मित्रों के हित में कार्य कर रही है और प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य और अनछुए पर्यटन गंतव्य का अनुभव प्रदान करना व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आजीविका के अवसर सृजित होंगे व पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रभावी तरीके से लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में इको–टूरिज्म गतिविधियों को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों, नदियों और कई ट्रेकिंग स्थलों को देखने के लिए प्रदेश में हर वर्ष 2 करोड़ से भी अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।

मुकेश अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नक्की में 2 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चन्द्र कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा का सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ज्वाली शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए करीब 16 करोड़ रूपए की शहरी जलापूर्ति योजना बनाई गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों में अच्छी पैदावार होने से उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में निर्माणाधीन फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ेगा।

धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य विद्युत बोर्ड को आत्मनिर्भर और दक्ष संगठन बनाने की दिशा में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के मुख्य अभियन्ताओं के साथ आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड को उपभोक्ता मित्र बनाकर आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और प्रायोगिक तौर पर धर्मशाला व शिमला शहर में स्मार्ट मीटर लगाने से राजस्व की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की कार्य प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को समायोजित किया जाएगा और इसके

लिए बोर्ड के आईटी विंग को भी अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में भारतीय लेखा मानक के अनुसार बोर्ड की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन करने पर भी विचार–विमर्श किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वे आज किन्नौर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान राजस्व मंत्री ने पाठशाला कानम के विद्यार्थियों को शिक्षा व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया। इस बीच जगत सिंह नेगी ने करीब 2 लाख रूपए की लागत से बनी कानम गांव से कानम डोगरी तक 6 किलोमीटर लम्बी एम्बुलैंस सड़क का लोकार्पण जबकि महिला मण्डल भवन कानम का शिलान्यास किया।

सुनील शर्मा

प्रदेश विश्वविद्यालय की तीन दिवसीय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज हमीरपुर जिले में अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में शुरू हुई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 53 कालेजों के लगभग 4 सौ 56 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बड़ी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री कालेज हमीरपुर में एमबीए की कक्षाएं आरंभ करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी और प्रदेश सरकार इस दिशा में निर्णय लेगी।

बस ट्रायल

चम्बा जिला की पांगी घाटी के दूरदराज गांव चस्क तक 3 किलोमीटर सड़क मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस का आज ट्रायल किया गया। पांगी के आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी ने बताया कि ट्रायल सफल रहा और गाँव वासियों को जल्द की बस सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सड़क मार्ग पर जरूरी सुधार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि लगभग 3 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर बसा चस्क गांव किलाड मुख्यालय़ से 37 किलोमीटर दूर है और सड़क ठीक न होने के कारण लोगों को बस सेवा की सुविधा नहीं मिल पा रही थी।